(c) Yes, Sir.

(d) to (g) Eight complaints have been received by the Delhi Administration in this regard and show cause notices have been issued to the permit holder under Section 86 of the Motor Vehicles Act, 1988.

D.T.C. buses

634. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the total number of D.T.C. buses plying on the roads to-date and the number of commuters who travelled in those buses during the period January-June, 1991;

(b) whether it is a fact that the number of D.T.C. buses have been reduced, if so the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to allow more private buses to cope with the rush in the capital, if so, the likely number thereof in proportion to D.T.C. buses?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) DTC had 3718 buses on road in June, 1991. Number of passengers carried daily (in lakhs) during the period January-June 1991 is given below :—

January, 1991	February, 1991	March, 1991
47.81	47.02	44.97
April, 1991	**May, 1991**	**June, 1991**
44.68	36.55	35.68

(b) There was a marginal decline of 4 buses during the period Jan.-June, 1991 due to scrapping of 4 over-aged buses which could not be replaced.

(c) 54 P.O. buses have been inducted during the current financial year. More number of private buses are not coming under D.T.C. due to unremunerative fare. The Delhi Administration have also been advised to grant additional stage carriage permits to private operators.

चकमा शरणार्थियों को वापस स्वदेश भेजा जाना

636. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या यह सच है कि बांगलादेश से आए लगभग 56,000 चकमा शरणार्थी अभी भी देश में त्रिपुरा राज्य में रह रहे हैं;

(ख) क्या हाल ही में बांगलादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन शरणार्थियों को वापस स्वदेश भेजे जाने के संबंध में बांगलादेश सरकार के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बातचीत कब हुई थी; और

(घ) उक्त बातचीत का क्या परिणाम निकला और क्या इन शरणार्थियों पर खर्च की जा रही धनराशि को बांगलादेश सरकार से वापस लेने के लिए भी कोई बातचीत की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां । इस समय त्रिपुरा में रह रहे बंगलादेश से आए चकमा शरणार्थियों की संख्या 53,154 है ।

(ख) जी, हां । बंगलादेश में अन्तरिम सरकार का गठन हो जाने पर इस मसले पर बंगलादेश के साथ विचार-विमर्श किया गया था । इसके बाद शरणार्थियों की

वापसी के तौर-तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए जिलाधिकारी, दक्षिणी त्रिपुरा तथा जिला आयुक्त, खागराचारी के स्तर पर अधिकारियों की बैठकें हुई।

(ग) उपर्युक्त बैठकें बंगलादेश में 11 फरवरी, 1991 तथा भारत में 1 फरवरी, 1991 को हुई थीं।

(घ) शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने (जिन्होंने पहली बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था लेकिन दूसरी बैठक में भाग लिया था) यह कहा था कि वे बंगलादेश में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों तथा उनकी मांगे पूरी न होने को देखते हुए वहां लौटने में असमर्थ हैं। शरणार्थियों के रहन-सहन पर खर्च हुई धनराशि बंगलादेश से मांगने के प्रश्न पर बंगलादेश के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी।

इंगलैंड में रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा दोहरी नागरिकता प्रदान किये जाने का अनुरोध

636. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड में रह रहे भारतीय मूल के लगभग दस लाख व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने की मांग करते हुए दोहरी नागरिकता प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंगलैंड में भारत के उच्चायुक्त ने भी इस संबंध में सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अभी तक कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) और (ख) भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों द्वारा समय-समय पर दोहरी नागरिकता प्रदान करने की मांग की जाती रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने मामले पर विचार किया और दोहरी नागरिकता की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया।

आकर्षक और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

637. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** क्या **जल-तथल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और विदेशी मुद्रा के बढ़ते हुए वर्तमान संकट को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक आकर्षक और आरामदायक बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में अभी तक कोई कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली प्रशासन से यह सिफारिश की है कि दिल्ली परिवहन निगम के भाड़े-ढांचे से ऊंचे भाड़े-ढांचे पर "स्पेशल स्टेज कैरिज परमिट की एक योजना लागू की जाए जो अधिक आरामदायक हो ताकि इस समय व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने वाले यात्रियों को अपने वाहनों से हटा कर सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग की ओर लाया जा सके। सार्वजनिक परिवहन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की रूप रेखाओं पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।